

(c) how the workers are to play their roles, details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the conclusions of the Seminar, the positive and active roles are :

- (i) Proper understanding of linkage between economic development and productivity leading to generation of more employment opportunities, control of inflationary trends and greater consumer satisfaction, and higher standards of living of the people.
- (ii) Ensuring that increase in wages has some relationship with increase in productivity.
- (iii) Meaningful influence over managerial decisions to promote and sustain economic viability of various organisations through participative management system.
- (iv) Creation of proper climate which promotes rather than hinders productivity.

(c) The workers can play a positive role by :

- (i) Education and training of members of trade unions and workers in the concepts, importance, methods of productivity and related areas.
- (ii) Strengthening of participative forums of management ;
- (iii) Creation of proper climate for promotion of productivity.
- (iv) Replacement of traditional collective bargaining by productivity agreements.

दूरदर्शन के लिए दहेज, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार, राष्ट्रीय एकता पर आधारित फिल्में

3344. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन निदेशालय का कुछ अनुभवी व्यक्तियों, गैर सरकारी संस्थानों संगठनों द्वारा दहेज, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार, राष्ट्रीय एकता आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर फिल्में बनवाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन व्यक्तियों तथा संगठनों के नाम क्या हैं जो इस वर्ष ऐसी फिल्में बनाएंगे और बनाई जाने वाली फिल्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाई गई फिल्मों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आई है तथा वे किस ध्येयों को लेकर बनाई गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दहेज, अस्पृश्यता, इत्यादि सहित सामाजिक महत्व के विषयों पर प्रख्यात बाहरी निर्माताओं से टी० वी० डाकुमेंट्री फिल्मों का निर्माण कराने की दूरदर्शन की योजना है। इसके अलावा, दूरदर्शन फिल्म प्रभाग, स्वयं दूरदर्शन और अन्य स्रोतों द्वारा इन विषयों पर तैयार की गई फिल्मों/डाकुमेंट्री फिल्मों, कार्यक्रमों इत्यादि को दिखा रहा है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1982-84 के दौरान बाहरी निर्माताओं द्वारा बनाई गई टी० वी० फिल्मों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	फिल्म का नाम	निर्माता का नाम	निर्माण वर्ष	लागत	विषय
1.	"सद्गति"	सत्यजित रे	1982-83	4,50,000/रु०	पिछड़े वर्गों का उत्थान ।
2.	"बंसी"	बाल गोविंद • श्रीवास्तव	1982-83	2,25,000/रु०	—तदेव—
3.	"दि कैटेलिस्ट्स"	शांति पी० चौधरी	1983-84		ग्रामीण स्वा- स्थ्य देखभाल विशेषकर परिवार कल्याण सम्बन्धी ।
4.	"मामु"	आनन्द महापात्र	1983-84		निरक्षरता उन्मूलन मद्य निषेध तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान का संदेश देती है ।
5.	दुल्हन ही दहेज	श्री आर० एम० शास्त्री संसद सदस्य	1983-84		दहेज विरोधी
6.	नई रोशनी	श्री जोगी कुमार	1983-84		अस्पृश्यता

**Year-Wise Details of Investments in  
Power Transmission and Generating  
During Sixth Plan**

3345 SHRI SOMNATH CHATTERJEE :  
Will the Minister of ENERGY be pleased  
to state :

(a) the details of investments in the  
power transmission and power generation in  
the Sixth Plan, with year-wise details of such  
investments ; and

(b) the details of any shortfall in the  
said investments during the same periods,  
if any ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI  
P. SHIV SHANKAR) : (a) and (b) Infor-  
mation is being collected and will be laid on  
the Table of the House,

**Postal Delivery System in Bombay**

3346. SHRI R. R. BHOLE : Will the  
Minister of COMMUNICATIONS be pleased  
to state :

(a) whether it is a fact that the Tele-  
phone Department earn a profit of about  
50 per cent of expenditure i.e. Rs. 360 crores  
out of total expenditure of Rs. 780 crores  
and this is all spent on Postal Department ;  
and

(b) whether Government are aware that  
postal deliveries are made in Bombay many  
times late by a week or two and whether  
such inefficient system should be allowed to  
continue to make both telephone and postal  
services useless ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE